सेक्टर-8 ईएसआई अस्पताल का पुनर्जीवन

कार्पोरेशन 12 करोड़ खर्च करेगी या बर्बाद

फ़रीदाबाद (म.मो.) चार दशक पूर्व ईएसआई कार्पोरेशन ने 10 एकड़ के भूखंड पर 200 बिस्तरों का अस्पताल बना कर हरियाणा सरकार को सौंपा था। समय-समय पर आई राज्य की नालायक व निकम्मी सरकारों ने मरीज़ो के इलाज करने की बजाय अस्पताल को ही मरीज बना दिया जो आज इसकी बिल्डिंग 'आईसीयू' में पड़ी है। इसे पुनर्जीवित करने के लिये कार्पोरेशन ने 12 करोड़ का बजट पास किया है।

विदित है कि 200 बिस्तरों के इस अस्पताल को सही ढंग से चलाने की नीयत हरियाणा में किसी भी सरकार की नहीं रही। रो-पीट कर इसे 50 बिस्तरों तक ही सीमित रखा गया। इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण तो यह है कि यहां कभी 15-20 से अधिक मरीज़ दाखिल नहीं रह सके। कारण ? इस अस्पताल में न तो पर्याप्त डॉक्टर व अन्य स्टाफ़ है और न ही आवश्यक उपकरण व दवायें आदि तो वहां मरने के लिये कौन भर्ती होगा ? अस्पताल के प्रति हरियाणा सरकार की इसी बेरुखी के चलते उस जमाने में मज़दूरों के करोड़ों रुपये से बने अस्पताल की बिल्डिंग पूरी तरह से दुर्दशा का शिकार हो चुकी है। पानी सप्लाई के लिये बनाई गई ओवरहेड टंकी इस कदर लड़खड़ा गई थी कि उसे जैसे-तैसे गिराकर ही पिंड छुड़ाना पड़ा।

अपनी बदहाली पर आंसू बहाता सैक्टर-8 का ईएसआई अस्पताल

आगे बढने से पहले पाठक ईएसआई स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने की व्यवस्था को समझ लें। यह व्यवस्था उस वाहन के समान है जिसका नियंत्रण दो ड्राइवरों के हाथ में है और मंजिल तक पहुंचने अथवा बीच रास्ते दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के लिये दोनों में से कोई जिम्मेवार नहीं। जी हां हकीकत यही है। ईएसआई एक्ट के मुताबिक मज़दूरों के वेतन से एक निर्धारित मात्रा में वसूली तो ईएसआई कार्पोरेशन करती है और राज्यों में स्वास्थ्य सेवायें चलाने का कार्य राज्य सरकारें करती हैं क्योंकि स्वास्थ्य सेवायें राज्य एवं संवर्ती सूची में आती हैं। इसकी एवज में कार्पोरेशन राज्य सरकारों को ईएसआई स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च का सात बटा आठ हिस्सा यानी आठ रुपये के खर्च में से सात रुपये कार्पोरेशन देगी व एक रुपया राज्य सरकार खर्चेगी। इसके लिये राज्य सरकार ने बाकायदा एक ईएसआई हेल्थकेयर निदेशालय बना रखा है। इसमें एक निदेशक एक उपनिदेशक व काफ़ी लम्बा-चौड़ा स्टाफ़ बैठा रखा है। यही निदेशालय राज्य भर के 25-30 लाख ईएसआई कवर्ड मज़दूरों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिये सालाना बजट बनाता है, हर तरह के स्टाफ़ की भर्ती करता है व हर तरह के आवश्यक उपकरण व दवायें आदि की खरीदारी करता है। दूसरी ओर कार्पोरेशन राज्य की डिमांड पर अस्पताल व डिस्पेंसरियों का निर्माण अपने खर्चे से करके राज्य को सौंपता है। लेकिन इसके बावजूद दोनों ही पक्षों में ताल-मेल का नितांत आभाव होने के चलते न तो कहीं पर्याप्त इमारतें हैं और न ही पर्याप्त स्टाफ़, उपकरण व दवायें उपलब्ध हैं। इसके लिये दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। जिसका दुष्परिणाम उन मज़दूरों को भुगतना पड़ता है जिनके वेतन से कार्पोरेशन नियमित वसूली करती रहती है।

सेक्टर आठ के अस्पताल पर 12 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च एक तरह से बर्बाद ही समझा जायेगा यदि इसे ढंग से न चलाया गया। राज्य सरकार से तो कोई उम्मीद अब रही नहीं, हां यदि कार्पोरेशन इसे टेकओवर करके खुद चलाये तो इस अस्पताल की कोई उपयोगिता हो सकती है। कार्पोरेशन के लिये यह कोई नया काम नहीं होगा। इसी शहर में एनएच तीन वाला अस्पताल भी कार्पोरेशन ने टेकओवर करके एक बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा शहर को दी है। इसके अलावा गुड़गावां के दोनों अस्पताल भी कार्पोरेशन खुद चला रही है। वह बात अलग है कि इन दोनों अस्पतालों की भी आज काफ़ी दुर्दशा है क्योंकि श्रमिकों की संख्या के मुकाबले इनकी क्षमता बहुत ही कम है। आज वहां भी फ़रीदाबाद की तरह 700 बिस्तरों वाले अस्पताल की जरूरत है।

सेक्टर 7 की जर्जर डिस्पेंसरी

करीब 45 वर्ष पूर्व सेक्टर 7 के दो एकड़ के प्लॉट में एक आलीशान डिस्पेंसरी कार्पोरेशन ने बनाकर हरियाणा सरकार को सौंपी थी। इतना ही नहीं डिस्पेंसरी के साथ डॉक्टरों के दो रिहायशी मकान भी बना कर दिये थे। ये मकान तो फ़िर भी कुछ हद तक ठीक-ठाक हैं जबकि डिस्पेंसरी की छत पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। तबाही का कारण छत पर लगातार बरसाती पानी का खड़ा रहना है। इसके चलते इस डिस्पेंसरी को अब खाली करके वीरान छोड़ दिया गया है और डिस्पेंसरी को सेक्टर आठ के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है।

यह पूछने वाला कोई नहीं है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग के खंडर बन जाने के लिये जिम्मेदार कौन है ? यदि यही बिल्डिंग वहां काम करने वाले डॉक्टरों या स्टाफ़ की अपनी निजी होती तो वे हर बरसात के बाद इसकी छत पर चढ़ कर या किसी को चढ़ा कर इसकी नियमित सफ़ाई ठीक वैसे ही कराते जैसे वे अपनी घर की कराते हैं।

एस्कॉर्ट कम्पनी ने मुख्य सड़क को ही बना डाला वाहनों पर लदा स्टोर

फ़रीदाबाद (म.मो.) सेक्टर 14 से सेक्टर 9 की ओर जाने वाली सड़क के एक किनारे एस्कॉर्ट ट्रेक्टर कम्पनी व इन्डियन ऑयल स्थित हैं तो दूसरे किनारे खेल परिसर एवं स्टेडियम आदि हैं। यह एक महत्वपूर्ण सड़क है। इसी सड़क से सेक्टर 14,15, 16,17,18 के निवासी सेक्टर 9,8,7 व 4 तक आते-जाते हैं। स्कूल खुले होने के दिनों में तो हज़ारों बच्चे साईकिलों व अन्य वाहनों द्वारा इस सड़क पर से आना-जाना करते हैं।

इतनी महत्वपूर्ण सड़क को उक्त ट्रैक्टर कम्पनी ने बाकायदा, न केवल अपनी निजी पार्किंग बना लिया है बल्कि एक तरह से स्टोर का रूप दे दिया है। सड़क पर हर समय दोनों ओर छोटे-बड़े हर तरह के वाहनों की लम्बी कतारें लगी रहती हैं। इनमें लम्बे-लम्बे ट्रक, छोटे कैंटर, माल वाहक तिपहिया व टैक्सियां आदि खड़ी रहती हैं। इन सभी वाहनों में वेन्डरों द्वारा निर्मित वह माल होता है जो कम्पनी द्वारा उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। कम्पनी के गेट पर बाकायदा एक लाउडस्पीकर द्वारा दूर-दूर तक, माल से लदे, वाहनों को उनके नाम व नम्बर से कम्पनी के भीतर आने के लिये पुकारा जाता है।

कम्पनी प्रबन्धन की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि पहले कम्पनी अपने स्टोर में दो से चार सप्ताह तक का माल भर कर रखती थी। लेकिन अब जीरो इन्वेंटरी पर कारखाना चलाया जा रहा है यानी स्टोर में कुछ भी रखने की कोई जरूरत नहीं है। वेन्डरों को अपने गेट पर लाइन लगवाकर खड़ा कर लिया जाता है क्योंकि कम्पनी के भीतर तो इतनी जगह नहीं होती कि इतने वाहनों को खड़ा किया जाय। इसके अलावा प्रबन्धन का यह अमानवीय रवैया भी रहता है कि जब सैंकड़ों वाहन कम्पनी के भीतर कई-कई घंटे खड़े रहेंगे तो सैंकड़ों वाहन चालक आदि उनकी टॉयलेट व कैन्टीन जैसी सुविधाओं का उपयोग करके कम्पनी का भार बढायेंगे।

कम्पनी केवल अपना स्वार्थ देखते हुये सार्वजनिक सड़क का दुरुपयोग तो कर ही रही है साथ में अपनी बारी की इन्तजार में खड़े वाहन चालक घंटो-घंटों तक परेशान रहते हैं। उन्हें न केवल उठाईगिरों व असामाजिक तत्वों से अपने वाहनों व उसमें लदे माल की हिफ़ाजत करनी पड़ती है बल्कि टॉयलेट आदि के लिये भी दायें-बायें भटकना पड़ता है। कुछ वाहनचालकों से बात-चीत करने पर इन बातों के अलावा उन्होंने जेबकतरों द्वारा उनकी जेब तराशी के बारे में भी बताया। एक चालक ने यह भी बताया कि थोड़ी सी चूक होने पर उठाईगिरा उसके वाहन की बैट्री ही ले उड़ा।

बिजनेस के चक्कर में वैन्डरों की तो यह मजबूरी है कि वे ट्रैक्टर कम्पनी को नाराज करके यहां पर वाहन खड़े करने से मना नहीं कर सकते। लेकिन पुलिस एवं ज़िला प्रशासन की ऐसी क्या मजबूरी है जो यह सड़क पूरी तरह से ट्रैक्टर कम्पनी के हवाले कर रखी है ? सड़क पर सदैव लगे रहने वाले जाम व वाहनों के आगे-पीछे होने व लापरवाही से इधर-उधर मुड़ने से अक्सर दुर्घटनायें भी होती रहती हैं।

सड़क को भी बनाया 'तिरंगा थीम'

तिरंगा थीम को घेरे बैठे बेखौफ ढाबे

फ़रीदाबाद (म.मो.) सरकार की विभिन्न एजेन्सियों- नगर निगम, स्मार्ट सिटी, एफ़एमडीए तथा 'हूडा' आदि द्वारा हजारों करोड़ रुपये विकास के नाम पर खर्च करने के बावजूद शहर की शायद ही कोई सड़क सही सलामत एवं गड्ढों से वंचित हो। वर्षा जैसा प्रकृति का वरदान शहर की जनता के लिये अभिशाप बनकर रह जाता है। शहर के तीनों अंडरपास लबालब पानी से भर जाते हैं, जिसके चलते लोगों को कई-कई किलोमीटर लम्बे चक्कर लगाने पड़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग सहित तमाम सड़कें इस कदर पानी में डूब जाती हैं कि तमाम वाहन रेंग-रेंग कर चलने को मजबूर हो जाते हैं। इससे न केवल समय की बर्बादी होती है बल्कि वाहनों द्वारा कई गुणा अधिक ईंधन फूंकने से धन एवं पर्यावरण की भी बर्बादी होती है।

जनता के ऊपर सरकार द्वारा थोपी गई उक्त मुसीबतों से ध्यान भटकाने के लिये सत्तारूढ़ नेता तरह-तरह के ड्रामे करते रहते हैं। ऐसा ही एक ड्रामा स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर व चंद विधायकों के नेतृत्व में इसी सप्ताह बडखल चौक पर किया गया। इसमें बताया गया कि चौक से लेकर बाईपास तक जाने वाली सड़क को जिसके एक ओर सेक्टर 28-29 व दूसरी ओर सेक्टर 19 स्थित है, 'तिरंगा थीम' का नाम दिया गया है। इस सड़क पर वाई-फ़ाई की सुविधा के अलावा साइकिल ट्रैक व फुटपाथ भी बनाया जायेगा।

विदित है कि बीते दो साल में करोड़ों रुपये खर्च करके इस अच्छी-भली सड़क को पहले खोदा गया व फ़िर बनाया गया। लेकिन बाईपास की ओर से आने वाले वाहनों को हाईवे पर आकर बल्लबगढ़ की ओर जाने के लिये सदैव जाम का सामना करना पड़ता है क्योंकि मोड़ पर तीन ढाबों ने सड़क पर कब्ज़ा करके यातायात अवरूद्ध कर रखा है। जाहिर है यह कब्जा राजनेताओं के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है।

रही बात वाई-फ़ाई, साइकिल ट्रैक व फुटपाथ की, तो यह सब शोशेबाजी केवल बजट डकारने के लिये की जा रही है। यहां किसी वाई-फ़ाई की जरूरत नहीं है, जहां तक बात साइकिल ट्रैक व फुटपाथ की है, तो ये सब जनता के हकूक हैं। ये किसी भी सभ्य समाज में सड़क निर्माण के साथ-साथ ही उपलब्ध करा दिये जाते हैं। इनके लिये कोई विशेष घोषणायें एवं ड्रामेबाजियों की आवश्यकता नहीं होती। जिस तरह के साइकिल ट्रैक की बात गूजर महोदय ने की है वैसे ही एक साइकिल ट्रैक की दुर्दशा का हाल यह है कि यह नज़र ही नहीं आता। उसे बाईपास से बाटामोड़ तक आने वाली सड़क के साथ-बीसियों लाख रुपये खर्च करके बनाया गया था।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06